



Ch 26/3/86

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३६]

नई दिल्ली, शनिवार, २८, १९८५/पृष्ठ ७, १९०७

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1985/PAUSA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के क्षेत्र में  
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—उण्ड ३—उप-उण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(हाथ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केंद्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories).

### भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, २० दिसम्बर, १९८५  
आदेश

आ.अ. 107 :—यह निर्वाचन आयोग ने अपने नारीख ७  
अक्टूबर १९८३ के आदेश नं. ७६/कर्नटक/४३ (४९-१२३) द्वारा  
जनवरी, १९८३ में हुए कर्नाटक विधान सभा के सावारण निर्वाचन में  
६०—गुड्डी विधान सभा निर्वाचन खेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अर्थव्यार्थ  
था नंजेंगीडा, मूल्हुर मर्ऱिटिवल, माशगुडा हूल्ही, गुड्डी नामुद, कर्नाटक,  
को मंसूद के किसी भी सदन के गां किसी गाउँ की विधान सभा अवधार  
विधान परिषद के मद्दस्य ने जान और हानि के लिए इस आदेश की  
नारीख से हीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्णीत घोषित किया था,

यह नारीख यह गत दिनों था कि श्री नंजेंगीडा, नं. ४-२-१९४३  
का लेखा संबंधी विवरण दाखिल कर दिया था :

यह श्री गौडा ने निर्णीत को चुनीनी देने हुए कर्नाटक उच्च  
न्यायालय में एक याचिका अर्जी (१९८५ की संख्या २४०१) दाखिल की  
और उच्च न्यायालय ने अपने नारीख ३ अक्टूबर १९८५ के आदेश द्वारा  
निर्णीत को रद्द कर दिया और आयोग को निर्देश दिया कि वह लेखा  
की संवीक्षा करें और विधि के अनुरूप इस विषय पर निर्णय करें।

और यह संवीक्षा करने पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि  
श्री गौडा ने निर्वाचन व्यायों का लेखा समय के भीतर और विधिएं द्वारा

अपेक्षित रूप में दाखिल कर दिया था और अक्टूबर जिला निर्वाचन  
प्रधिकारी द्वारा पहले ही गई रिपोर्ट, कि श्री गौडा ने कोई लेखा दाखिल  
नहीं किया, के आधार पर दिए गए उपर्युक्त आदेश को रद्द करने का  
निर्णय किया था ;

अत. यह नियंत्रित आयोग नाम: उत्तराखण्ड अधिनियम, १९५५ की  
धारा १०३, साधारण खांड अधिनियम, १८९७ की धारा ३। के अधीन  
आयोग को प्रदत्त मत्कियों का प्रयोग करने हुए और इस संबंध में प्राप्त  
अन्य मत्कियों का प्रयोग करने हुए, एनद्वारा आनंद, नारीख ७ अक्टूबर,  
१९८३ के आदेश में नियंत्रित मत्किय करने का निर्देश देता है :—

“आवेदन के नीचे ही गई सारणी में कम से १०५ के मामतेवाली गई<sup>१</sup>  
प्रविटियों समाप्त कर दी जाएँगी। कम संख्या १०६ से १२३ तक  
को १०५ से १२२ तक पुनः सख्तीयता दिया जाएगा।”

उपर्युक्त मत्किय ७ अक्टूबर, १९८३ से प्रभावी समझा जाएगा।

[नं. ७६/कर्नटक/४३]

आदेश से,

सी.एल. राज सिंह  
भारत निर्वाचन आयोग

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 20th December, 1985

## ORDER

O.N. 107.—Whereas the Election Commission vide its Order No. 76/KT/83(89-123) dated the 7th October, 1983 had disqualified Shri Nanjegowda S/o Marisiddiah, Sagaranahalli, Gubbi taluk, Karnataka, contesting candidate at the general election to the Karnataka Legislative Assembly held in January, 1983 from 60-Gubbi Assembly Constituency for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of that order;

Whereas it subsequently transpired that Shri Nanjegowda has filed a statement of account on 4-2-1983:

Whereas Shri Gowda filed a writ petition before the Karnataka High Court (No. 2401 of 1985) challenging the disqualification and the High Court quashed the disqualification Order vide its order 3rd October, 1983 and directed the Commission to scrutinise the account and decided the subject in accordance with the law;

And whereas on scrutiny, the Commission is satisfied that Shri Gowda has filed the account of election expenses within the time and in the manner required by law and accordingly decided to annul the above order made on the basis of the earlier report of the District Election Officer that Shri Gowda had not filed any account;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on the Commission under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling the Commission in that behalf, the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its order dated the 7th October, 1983:—

"In the Table below the entries against Serial No. 105 shall be deleted. The Serial Nos. 106 to 123 shall be renumbered as 105 to 122".

The above amendment shall be deemed to be effective with effect from 7th October, 1983.

[No. 76/KT/85]

By Order,

C. L. ROSE, Secy.  
Election Commission of India